[श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल]

मैं कहूंगा और मैंने आपको हाऊस के बाहर भी यह बात कही थी कि वह वाक्या उस तरह का नहीं है । इसलिए मेरा खयाल है कि इस बहस को बंद करके आज कश्मीर जैसे अहम मसले पर बोल रहे हैं, उस पर ज्यादा बात करें।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदया, मैं उसकी बात करूंगा, पर आपने चेयर से कल चन्द बातें कही हैं.... **(व्यवधान)** ....

उपसभापति अब आप कल की चेयर की बात करेंगे अहलुवालिया जी तो you will be at a disadvantage because I have the record before me.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Yes, you go through the record.

THE DEPUTY CHAIRMAN: And it shows that you say because he belongs to a minority community...But he says the policeman did not know that he is from the minority community. Then how can you, who were not present at that place, make such an allegation?

SHRI S. S. AHLUWALIA: You never allowed me to complete my sentence

1.00 P.M.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you to complete your speech. And that matter is over.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, I am about to say.....

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not know what you are about to say. (*Interruptions*)

SHRI S. S. AHLUWALIA: He is a senior journalist. He belongs to a minority community. Above all, he is a Member of Parliament.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Do not try to unnecessarily twist the thing. Let us forget about what happened yesterday, and let us deal with the present.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया महोदया, आपने आज चेयर से..... **(व्यवधान)**

उपसभापति : देखिये हाउस बंद होने वाला है,

I did not raise the issue. It is Mr. Fotedar who raised it.

I adjourn the House for lunch till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-six minutes past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): in the Chair.

RESOLUTION RE: RECURRING FLOODS IN BIHAR—(Contd.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We shall now proceed with the Private Members' Resolution moved by Shrimati Kamla Sinha. I believe when we adjourned last time Mr. Md. Salim was in the midst of his speech. Now he will continue his speech.

श्री महोम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बातें के बारे में कह रहा था वह यह थी कि बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए एक तरफ जैसा हमारा सामाजिक नज़रिया होना चाहिए, वैसे ही जनता की जो भागीदारी है, इसकी भी हमारी योजना में स्वीकार करना पड़ेगा । इस के लिए भी जो लोकल अथारिटीज हैं चाहे वह पंचायत हो या जिला परिषद हो, उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल करना पड़ेगा खासकर उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए । बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए अगर हम पीसमील सोचते हैं, टुकड़े टुकड़े करके सोचते हैं या हर साल बाढ़ आए उसके बाद विचार करते हैं, एक एक

राज्य के बारे में, एक एक नदी के बारे में सोचते हैं तो हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमें उसी तरह से सोचना चाहिए जिससे कि बाढ़ को स्थायी रूप से रोकथाम हो सके, इसका परमेनेंट सौल्यूशन किया जाए, यह हर साल की समस्या न रहे, यह बाढ़ रोकने की समस्या नहीं, हमारे मुल्क के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए, हमारी जो भूमि है उसका सही व्यवहार करने की योजना होनी चाहिए ताकि वह लंबे अरसे तक अच्छे ढंग से हमारी सेवा में आ सके । इसके लिए हमारा नेशनल फ्लड कंट्रोल और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका सही लाभ हम नहीं उठा सके हैं । मैं उस रोज़ टी०वी०सी० के बारे में कह रहा था खासकर जब मध्य बिहार और उत्तर बिहार की बाढ़ की समस्या है तो हम यह देखते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल और उत्तर बिहार के क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो हमारे जो डैम हैं चाहे वह पंचाली हो, चाहे वह मपडौर हो, फ़रक्का बैराज हो या पलइया हो, जब नदी फुल रहती है तो हम हजारों क्यूसेक पानी छोड़ते हैं । मैं बंगाल से आता हूं वहां पिछले साल 72 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया जब कि वहां वैसे ही काफ़ी पानी आ गया । हम डैम से भी पानी छोड़ते रहते हैं तो इसका सही लाभ उठाने के बजाय नुकसान होता रहा है । इनकी सही मेंटिनेंस भी होनी चाहिए और सही थेटीनेंस भी होना चाहिए । इसकी तरफ़ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और बाढ़ से जो नुकसान है उसमें कमी लाने के लिए जो वैज्ञानिक प्रगति है, उसके अनुसार सही फ़ोरकास्ट के लिए हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा । सिर्फ़ फ़ोरकास्ट करने से काम नहीं चलेगा बल्कि राज्य सरकारों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा । जनता को, गांव को बचाने के बाद उनको रिलीज कैम्प में ले जाने पर नजर डालनी पड़ेगी ।

इसके साथ-साथ बाढ़ जब आती है तो हम देखते हैं कि खाने की किल्लत हो जाती है और इस से कुछ दूसरे लोग लाभ उठाते हैं तो ऐसी सिच्युएशन में हमें रेगुलर फूड सप्लाई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा । जो क्षति इससे हमारी होती है उसका एक साइंटिफिक असेसमेंट करने का बंदोबस्त करना पड़ेगा । एक लौंग फिगर दे दो तो इससे काम नहीं चलेगा । आज के समय सबसे बड़ी समस्या वहां के पुनर्गठन की है । इस बारे में भी सही ध्यान देना पड़ेगा । मैं यह बात इस लिए कह रहा हूं पिछली बार जब बाढ़ आयी थी तो काफी हालत बिगड़ी थी । सिर्फ बिहार की बाढ़ की बात नहीं है ऐसा और जगह भी होता है और यह हर साल होता है । हमें शर्म आनी चाहिए कि आजादी के 42 साल बाद भी एरिया के बारे में एक खबर आयी थी कि एक मां अपने बच्चे को बेच रही है । बाढ़ आयी नहीं है, फोरकास्ट किया गया है कि बाढ़ आयेगी । पानी खतरे के प्वाइंट से ऊपर उठ आया है बच्चे को इसलिए नहीं बेच रही है कि बच्चा बच जायेगा बल्कि इसलिए कि बाढ़ के आने से पता नहीं कुछ बचेगा या नहीं इसलिए हाथ में कुछ पैसा तो होना चाहिए। यह हमारे लिए दर्दनाक और शर्मनाक बात है । मैं इसके साथ यह भी जोड़ना चाहता हूं कि जब बिहार को बाढ़ के बारे में सोच रहे हैं तो हमें असम, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में भी सोचना चाहिए यहां पर भी बाढ़ से काफी नुकसान होता है। अब तक हम बांध निर्माण की बात सोचते थे, बांध तो बनाने पड़ेंगे और उनको मेन्टेन करना पड़ेगा लेकिन पानी को स्टोर करने के लिए रिजवायर बनाने पर भी जोर डालना चाहिए ताकि हम उस पानी को बाद में इस्तेमाल कर सकें । वह स्टोरेज वाटर इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए और बिजली का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए । साथ-साथ जो रिजवायर बनेगा वह सिर्फ पानी के ठहराव के लिए ही नहीं होगा बल्कि गांव के लिए एक ऊंचा बांध भी बनेगा जिससे गांव के लोगों को रास्क न हो क्योंकि उनको वहां से उठाकर कहीं और ले जाने की समस्या होती है । इस लिए अगर बाढ़ के पानी को रोकने के लिए रिजवायर बनाते हैं तो काफी ऊंचा बांध भी बन जाता है वहां लोगों को

[श्री मोहम्मद सलीम]

बाढ़ के मौके पर ठहराया भी जा सकता है।

इसके साथ-साथ लैंड इरोजन की बात भी आती है। मैं बंगाल से आता हूं। मुर्शीदाबाद में यह लगातार समस्या है। इसकी रोकथाम के लिए हमें कोशिश करनी होगी, इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और वह जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार अपने ऊपर ले। आपको पता है गांव धंसे जा रहे हैं। मुर्शीदाबाद का एरिया जो गंगा के किनारे है वहां पर सायल कंजवशन के काम पर जोर देना पड़ेगा। इसके लिए स्टेट के फारेस्ट डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बातचीत करके एक्शन प्रोग्राम बनाना होगा। काफी अरसे से रीवर बेसिन का प्रोजेक्ट, बांध का प्रोजेक्ट बाढ़ रोकन की योजनायें चल रही हैं इन योजनाओं पर स्पीडी वर्क के लिए जोर देना पड़ेगा चाहे वह बंगाल में हो, असम में हो, असम में ही, नार्थ बिहार में हो। बरसों पहले कमेटी की रिपोर्ट थी उसके बाद काफी योजनायें बनीं लेकिन हम उसका सही लाभ तभी उठा पायेंगे जब टाइम बाउंड प्रोग्राम लेकर सही ढंग से कम्पलीट कर पायें, खत्म कर पायें। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो यह संकल्प है, बेहतर होता यह सिर्फ बिहार के बारे में ही न होकर पूरे देश के नजरिये से और सामूहिक तौर पर होता। बिहार की बाढ़ की समस्या सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, आसाम की बाढ की समस्या सिर्फ आसाम की समस्या नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की समस्यायें हैं। इसके लिए हमें सामूहिक नजरिया तैयार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ नेशनल केलेमिटीज फण्ड का जो काम शुरू किया गया है, इससे लाभ हुआ है।

बाढ के साथ साथ मैं एक दूसरी बात की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। खास कर पहाड़ी इलाकों में लैण्ड स्लाइड होती हैं जससे बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। पहाड़ों में सौयल कजरवेशन का काम भी होना चाहिए। पेड़-पौधों का भी सवाल हैं। पिछले महीने पौड़ी गढ़वाल में तलाई गांव में लैंड स्लाइड हुआ जिसमें सारा गांव का गांव बह गया। इसलिए इसके साथ में इसको भी जोड़ देता हूं। हमें इसमें सामूहिक नजरिया अपनाना चाहिए और पहाड़ों से लेकर समुद्र तक जो प्रकृति की देन हैं उसका सही रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और पानी का लाभ उठाना चाहिए ताकि बाढ से हमें रोना न पड़े और पानी जो प्रकृति की बहुत बड़ी देन है उसका लाभ देश की उन्नति के लिए किया जाना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भारकर अन्नाजी मासोदकर) : श्री शंकर दयाल सिंह अनुपस्थित।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जो अशासकीय प्रस्ताव हमारी बहिन सदस्या श्रीमती कमला सिन्हा जी लाई हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार की समस्या इस सदन में उन्होंने रखी है। यह बिहार की ही समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। इस प्रस्ताव में लिखा है कि बिहार की अधिकांश नदियों के उदगम स्थल नेपाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हैं, इस कारण बिहार राज्य निरंतर बाढ़ की चपेट में रहता है जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावि देश के कुल क्षेत्र का लगभग 56.57 प्रतिशत उस राज्य का होता है, यह सभा राज्य में विशेषत: उत्तर तथा मध्य बिहार में विनाशकारी बाढ़ की वर्तमान स्थिति पर अपनी गंभीर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती हैं कि वह इस राज्य को प्रति वर्ष बाढ़ से होने वाली तबाही से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभावी उपचारी कदम उठाये। यह जो 56 प्रतिशत या 57 प्रतिशत जमीन हैं वह बाढ़ से प्रभावित होती हैं। बिहार हमारे भारत की सांस्कृतिक देन का उदगम स्थल हैं। बिहार में महात्मा गौतम बुद्ध, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, बाबू जयप्रकाश नारायण और बाबू जगजीवन राम जैसे महान लोग इसी पवित्र भूमि में पैदा हुए। मगर हम देखते हैं कि बिहार की 57 प्रतिशत भूमि बाढ़ में बैठ जाती हैं। यही कारण हैं कि

वहां गरीबी है और दरिद्रता का रेशियों भी वहां दिन प्रति दिन बढता जा रहा है। अगर हम इस 50 प्रतिशत से भी अधिक भूमि की रक्षा कर लेते हैं तो कृषि का उत्पादन हम दुगुना कर सकते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत को जब हम महाराष्ट्र के लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मीलों तक कोई पर्वत नहीं हैं और जमीन लेवल पर हैं जो कृषि के लिए बहुत ही अच्छी हैं। पानी भी यहां बहुत है। हमारे महाराष्ट्र में दो सौ, तीन सौ मीटर नीचे खोदना पडता है तब कहीं जाकर पानी निकलता है, लेकिन उत्तर भारत में 15 या 20 फुट की गहराई में पानी मिल जाता है। ऐसी स्थिति होते हुए भी और इतनी अच्छी जमीन होते हुए भी यहां पर गरीबी है। इस पर हमें गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिए। पिछले 40-42 वर्षों से यह स्थिति चल रही है और इस बाढ़ का हम इलाज नहीं कर सके हैं। यह हमारे देश के लिए गम्भीर बात है और बहुत बड़ा खतरा भी है। हम जानते हैं कि नदियां पहाड़ों से निकल कर समुद्र में जाती हैं। चाहे गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, सिन्धु हो या राजी या व्यास हों, इनके बारे में काफी साहित्य लिखा गया है। इसमें कितना पानी है। इस हिमालय के पानी की वजह से उत्तर भारत की सारी भूमि सुजलाम् सुफ़लाम् होती है और हम पानी की एक-एक बूंद के लिये तरसते हैं, दक्षिण भारत में और विशेष कर महाराष्ट्र में। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि गुजरात के सौराष्ट्र की भूमि में दो-दो, चार-चार साल तक वर्षा नहीं होती। वह सदैव सूखे की चपेट में रहता है। गरीब लोग, किसान भूखे प्यासे तरसते हैं और सरकार को वहां करोड़ो रुपया खर्च करना पड़ता है। एक तरफ़ बाढ़ आ रही है, एक तरफ़ बानी से जमीन बह रही है और दूसरी तरफ़ लोगों को सालों साल पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। इस विषमता को हमें नष्ट करना है। हमें राजनीति से ऊपर उठकर इसके बारे में सोचना चाहिये। जब इस देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना बनी तो इस सदन के अन्दर मैंने कई बार कहा कि हमारी योजना कृषि और इरीगेशन, सिंचाई के लिये बननी चाहिये। जब तक भूमि की जो प्यास है, उसे जल की जो जरूरत है वह पूरी नहीं होगी तब तक हमारे देश में सुजलाम सुफ़लाम का जो इतिहास स्वर्णक्षरों में लिखा हुआ है उसको कोई मतलब नहीं होगा। कई बड़ी-बड़ी नदियों का पानी पाकिस्तान चला गया, उससे उनकी भूमि की सिंचाई हो रही है। आज भी उत्तर भारत की कुछ नदियां हैं जो बिहार में मिट्टी बहा रही हैं। इसके लिये हमने कितना खर्च किया है ? इसको रोकने के लिये हमने जो पैसा खर्च किया है और जो आगे खर्च किये जाने वाला है, इसके लिये हमें तीन बातों की तरफ़ ध्यान देना चाहिये। एक इरीगेशन; दूसरा पावर और तीसरा अग्रीकल्चर। जैसा कि एग्रीकल्चर में कहते हैं एम०पी०पी० नाइट्रोजन, फ़ारफ़ोरस, और पोटाश। नाइट्रोजन जीवन का एक महत्वपूर्ण एलीमेंट है। नाइट्रोजन वनस्पति के लिये, प्राणी के लिये या मनुष्य के लिये जरूरी है। हाईड्रोजन, कार्बन और आक्सीजन बाईलाजीकल लाइफ इनसे बनी है। तो जो ये बातें हैं, जो नैसर्गिक हैं, इनसे दुनिया भरी पड़ी है। इनसे जिनसे हमारी हानि होती है, उसको कैसे रोका जाय, यह सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। उपसभाध्यक्ष महोदय, गंगा नदी बहुत पवित्र नदी मानी जाती है और त्योहारों में लोग गंगा में नहाने जाते हैं, गोदावरी में नहाते हैं, कृष्णा में नहाते हैं। नहाने से यह पवित्रता का जो भाव है वह इसलिये नहीं है कि नहाने से पाप धुल जाता है। बल्कि पवित्रता इस चीज से है कि उसके पानी से अनाज पैदा होता है और उसके कारण उनकी रोटी-कपड़ा और मकान की समस्या हल होती है। इसमें उसकी पवित्रता है। हम इस बात को नहीं समझे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में जो लिखा है उस पर न जाकर हमने उनकी मूर्तियों को मंदिर में बिठा दिया। हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, जो उच्च गुरू हैं, मैं किसी जाति पर दोष नहीं लगाना चाहता, लेकिन जो पंडित लोग हैं उन्होंने भगवान

[श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव]

कृष्ण को मंदिरों में बन्दी बना दिया। नदियों का पानी खेतों के लिये, पौधों को उगाने के लिये है और मानव जीवन के लिये है। अगर मानव जीवन के लिये उस पानी का उपयोग न किया जाये तो उस पानी का और उस नदी का पवित्रता का कोई मतलब नहीं है।

महोदय, इस सरकार ने कहा है कि हम आठवीं योजना में 50 प्रतिशत पूंजी कृषि पर लगायेंगे, देहातों में लगायेंगे। यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कृषि में क्या लगने वाला है और कितना लगने वाला है। आपकी प्रायरिटीज क्या है? आपकी प्रायरिटीज में कृषि यानी एग्रीकल्चर, इरीगेशन, पावर और ग्रामोद्योग होना चाहिये। ग्रामोद्योग का मतलब खादी नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी उद्योग चल सकते हैं ऐसे सारे उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में जायें। डीसेन्ट्रलाइजेशन आफ़ दि इंडस्ट्री दैट व्हट आई वांट। इस तरह का अगर कार्य किया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे हमारा उद्देश्य काफ़ी हद तक सफ़ल हो सकता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गोमती, नर्वदा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा ऐसी कितनी बड़ी बड़ी नदियां हमारे देश में है। लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा नदियों गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गोमती इन सारी नदियों से बिहार बाढ़ से प्रभावित होता है। इसको अगर रोकना है, तो शायद आप को मालूम होगा उपसभाध्यक्ष महोदय कि हमारे देश में एक जो सिंचाई मंत्री थे, डा० के०एल० राव, वे बहुत बड़े इंजीनियर भी थे, उन्होंने गवर्नमेंट को यह सजेस्ट किया था कि आप गंगा-कावेरी लिंक योजना को मंजूरी दें। उस वक्त इसकी कीमत 10 हजार करोड़ थी। अब मैं समझता हूं कि उसकी कीमत 1 लाख 20 हजार करोड़ हो गई है। अगर गंगा-कावेरी लिंक योजना को उस वक्त स्वीकार कर लिया जाता तो हिन्दुस्तान की साढ़े तीन करोड़ भूमि को पानी मिल सकता था। और आधी दुनियां को हिन्दुस्तान अनाज दे सकता था। इससे हमारे देश में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी प्रभावी हो सकता था। मगर इसको स्वीकार नहीं किया गया। एक कहावत है देर आयाद दुरुस्त आयाद। मैं आपके माध्यम से सरकार से और सिंचाई मंत्री जी से जो यहां बैठे हैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे कितनी देर हो जाये मगर गंगा कावेरी योजना को स्वीकार करना चाहिये उत्तर भारत में जो बहने वाला पानी है इस पानी में मिट्टी भी बह जाती है और इस मिट्टी से बना हुआ इंसान भी बह जाता है। अगर इंसान की जिन्दगी बचानी है तो इस पानी का सदुपयोग करना चाहिये। अगर पानी का सदुपयोग करना है तो लिंकिंग आफ़ रीवर्ज, एक दूसरे से नदियों को जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक बाढ़ का समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप जानते हैं, उपसभाध्यक्ष महोदय, आप भी महाराष्ट्र से आते हैं और मैं भी महाराष्ट्र से आता हूं, बिहार में पानी बह जाता है लेकिन हम को महाराष्ट्र में पानी नहीं मिलता है। अभी 15 अगस्त को प्रधान मंत्री ने कहा कि मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा कि सौराष्ट्र में जाकर बरसें।

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : बरस गये।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : बरस गये, इसलिये मैं ईश्वर को और प्रधानमंत्री को दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि सौराष्ट्र में ही नहीं मगर इस देश के जितने सूखे प्रांत हैं वहां जाकर बादल बरसें। पता नहीं प्रधानमंत्री बहुत पुण्यवान है हमारा कोई पुण्य नहीं है इसलिये हमारी तो भगवान सुनता नहीं है (व्यवधान)

श्री ज.दीश प्रसाद माथुर : (उत्तर प्रदेश) : उन्होंने भगवान को टंक काल लगाया था।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : माथुर साहब ने कहा कि भगवान को ट्रंक काल लगाया । हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम इतना इफ़ेक्टिव है कि भगवान के सिवाय किसी को ट्रंक काल लगता ही नहीं है । फिर भी भगवान से आपने जो नाता जोड़ा है आपको भगवान बचाये, यह मैं शुभ कामनायें देता हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां नर्मदा सागर डैम का काम चल रहा है। सरदार सरोवर, जैसे कि सरदार पटेल को भारत का फ़ौलादी पुरुष कहा जाता है वैसे ही नर्मदा डैम पर तैयार होने वाला जो सरदार सरोवर है यह हिन्दुस्तान का सेबसे बड़ा सरोवर है, । मैं किसान होने के नाते जानता हूं कि Poverty is the greatest pollution in the country.

कोई इनवायर्नमेंट के नाम पर, कोई वृक्षों के नाम पर आन्दोलन करके उसको दबाना चाहते हैं । मैं इसके खिलाफ़ हूं । सवाल यह हैं कि जितने वृक्ष गये हम उतने वृक्ष लगा सकते हैं मगर 17·5 लाख हैक्टेयर जमीन पर किसानों को जब पानी मिलेगा और वहां से जो उत्पादन होगा तो उससे वह देश की आधी से ज्यादा आबादी को अनाज पैदा करके खिला सकेंगे । इतनी बड़ी सरदार सरोवर योजना है। मैं उसका पुरी तरह से समर्थ करता हूं । कुछ स्वार्थी लोग हैं, कुछ शहरी लोग हैं जो यह चाहते हैं कि किसानों की तरफ़ पानी न जाय और गांवों का विकास न हो जिससे उनका राज चलता रहे। मैं इस का विरोध करता हूं। मैं नर्मदा सागर प्रोजेक्ट का पूरी तरह से समर्थन करता हूं । उपसभाध्यक्ष महोदय, आप भी महाराष्ट्र से आते हैं और मैं भी महाराष्ट्र से आता हूं। मैंने एक प्रश्न पूछा था इस सदन में कि महाराष्ट्र की सिंचाई क्षमता कितनी है और पूरे देश की सिंचाई क्षमता कितनी है। उसका जवाब यह आया कि पूरे देश की सिंचाई क्षमता सभी प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद 113 मिलियन हैक्टेयर की है और मार्च, 1990 तक 78.79 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई क्षमता पूरी हो जायेगी । इसका मतलब यह हैं कि 34 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई के लिये अभी काम करना बाकी है। महाराष्ट्र के बारे में देखिये, महाराष्ट्र कितना पीछे है । पूरे देश की सिंचाई क्षमता 113 मिलियन हैक्टेयर हैं और महाराष्ट्र के सारे रिसोर्सेज टैप करने के बाद भी 7.3 मिलियन हैक्टेयर जमीन में हम पानी दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में जितनी सिंचाई हम कर सकते हैं उका सिर्फ़ पांच प्रतिशत सारे रिसोर्सेज टैप करने के बाद महाराष्ट्र में हम सिंचाई कर सकते हैं । मगर फ़िर भी आज तक महाराष्ट्र में कितनी क्षमता पूरी हुई है, कितनी सिंचाई हुई है, 4.42 मिलियन हैक्टेयर **(समय की घंटी)** उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की 42 से ज्यादा मीडियम और मेजर प्रोजेक्टस वाटर रिसोर्सेज अथारिटी की क्लीयरेंस न मिलने के कारण, पैसा न मिलने के कारण केन्द्र सरकार के पास पड़ी हुई हैं। यह बहुत ही दुखद बात है कि महाराष्ट्र में सिर्फ़ पांच प्रतिशत सिंचाई क्षमता है और यह छत्रपति शिवाजी और बाबा साहब अम्बेदकर की कर्म भूमि और जन्म भूमि है । जो हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा कपास पैदा करता है, सबसे ज्यादा चीनी पैदा करता है, सबसे ज्यादा ज्वार पैदा करता है, सबसे ज्यादा रागी ? पैदा करता है, दूसरे नम्बर पर ग्राउंड नट पैदा करता है, ग्रेप्स पैदा करता है—महाराष्ट्र के जो किसान हैं उन्होंने इतना परिश्रम करके अपने राज्य को इस देश में अग्रपर बनाया है— उस महाराष्ट्र में 5 प्रतिशत क्षमता है मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र की जो सिंचाई योजनाएँ हैं वे वार फ़ूटिंग पर पूरी होनें चाहिये । अभी 4.2 मिलियन हैक्टेयर है । मतलब 42 लाख हैक्टेयर जमीन को हम पानी दे सकते हैं और अभी 30 लाख हैक्टेयर में पानी देना है । पांच साल के अन्दर, आठवीं पंच वर्षीय योजना में महाराष्ट्र के सिंचाई के जो भी प्रकल्प हैं वे पूरे करने चाहिये । अगर आपकी सरकार ने यह किया है तो मैं आपका इस सदन के अन्दर अभिनन्दन करूंगा, शायद 5 साल के

[श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव]

बाद में नहीं रहूं। मैं तो जरूर रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : बाढ़ के बारे में बोलिये।

श्री विठ्ठलभाई माधवराव जाधव: अभी हाल में 87,500 हैक्टेयर सिंचाई की क्षमता सृजित कर दी गयी है यह बहुत ही गंभीर समस्या है। अभी मैंने नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में कहा, महाराष्ट्र के बारे में कहा। अगर गंगा कावेरी लिंक योजना पूरी की जाय तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत इस तरह से जुड़ जायेंगे जैसे हम अपने हृदय से जुड़े हैं। हमारा हृदय और आंखें दोनों जुड़ जायेंगे। भारत की संस्कृति नदियों से उद्गमित होती है और नदियां सागर में मिलती हैं। यदि सारी नदियां जोड़ दी जायें तो भारत की संस्कृति एक हो जायेगी। विशाल भारत होगा और शुजलाम सुफलाम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, Mr. Sarda Mohanty.

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Resolution moved by Shrimati Kamla Sinha is a very important one and I support it.

Sir, agriculture has been given the topmost priority in our current Five Year Plan and it is to attain self-sufficiency in foodgrains and agricultural produce so that we can avoid importing anything from other countries by spending our foreign exchange and secondly, to earn foreign exchange by exporting our excess production. But we will not be able to achieve our goal unless and until we are able to tackle the twin problem of drought and floods.

Sir, Orissa is also one of the States which are affected by drought and floods like Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Tripura West Bengal, etc. In the district of Kalahandi, due to drought, people were forced to sell their wives and children in order to save themselves from starvation.

Sir, deforestation is the main reason for floods and drought in our country. In order to overcome drought, we have to take proper steps for afforestation. Certainly due to deforestation, more silt is being formed in the rivers and our riverbeds are filled with silt only and, as a result, the rivers have lost their capacity to contain the excess flood waters as they were doing previously. There is another factor also. The mouths of our rivers are also full of silt and, therefore, they have lost their capacity to discharge the waters into the sea. For these reasons, flood is inevitable. We have built some dams in order to control the floods and also to produce electricity and for irrigation. But these dams are not properly maintained. Year after year they are filled up with silt and we have not taken steps to remove the silt in these dams. Therefore, these dams also have lost their capacity to contain more water. Since desilting has not been done properly, the capacity of the reservoirs and dams to store more water is diminishing day by day and the excess water is discharged into the rivers which causes floods. In order to tackle the problems of floods and drought, afforestation is very essential, removal of silt is very necessary and construction of small dams is needed. I feel that these three things are very essential if we have to tackle successfully the problems of drought and floods.

With these words, Sir, I support this Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, Mr. Chaturanan Mishra.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती कमला सिन्हा जी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने एक बहुत ही अहम सवाल पर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। बिहार में हर साल बाढ़ भी

आती है और सुखाड़ी भी आता है। बाढ़ का पानी जब हम रोक नहीं पाते हैं, और बारिश जब खत्म हो जाती है, तो हम सुखाड़ के शिकार हो जाते हैं।

इसलिए वहां बाढ़ भी है, वहां सुखाड़ भी है, बिहार में इतना पानी है कि हम शायद भारत के बहुत बड़े हिस्से को वह पानी दे सकते हैं। लेकिन बिहार की क्षमता नहीं है कि उस पानी का इस्तेमाल करे।

अभी कई माननीय सदस्यों ने गंगा-कावेरी योजना की चर्चा की। भारत सरकार अगर इसको प्रारंभ करें, प्रारंभ तो कर सकती है, भारत सरकार के वित्तीय साधन के परे है कि वह इस योजना को ले सके।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : यह बहुत दिनों से योजना है।

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : यह श्री के० एल० राव जी ने.....

श्री चतुरानन मिश्र : के०एल० राव साहब ने इसको शुरू किया था। तो यह योजना बहुत दिनों से है। **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : इसके बारे में तो मिनस्टिर साहब बतलायेंगे।

श्री चतुरानन मिश्र : उसके लिए हम रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसे पूरा करना संभव नहीं है। शुरूआत अगर करें, तो यह बात हो सकती हैं लेकिन कंप्लीट करना जो हैं, वह हमारे लिहाज से एक सरकार द्वारा एक पांच साला योजना में होने वाला नहीं है। वह कई पंचवर्षीय योजनाओं में होगा।

एक माननीय सदस्य : इसके लिए चार योजनाए चाहिएं।

श्री चतुरानन मिश्र : वहीं हम आपसे कह रहे हैं कि कई योजनायें...

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : तो क्या यह एक सरकार के समय में नहीं होने वाला है।

श्री चतुरानन मिश्र : यह कैसे हो सकेगा. आप जैसा विद्वान आदमी सोचे कि पांच वर्ष के अंदर ही यह कार्य कर लेंगे, इसके पहले भी तो चालीस वर्ष कोई यहां पर थे। उनकी भी वही पवित्र इच्छा रही होगी, ऐसी बात नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मैंने पांच वर्ष तो नहीं कहा है। मैंने कहा कि योजना शुरू की जाए।

श्री चतुरानन मिश्र : ...**(व्यवधान)** मेरा ख्याल है कि इसके लिए जो साधन की जरूरत होगी, क्योंकि विदेश से ये नदियां आती हैं, नेपाल से, अब ब्रह्मपुत्र तो चीन की टेरोटरी से शुरू होकर आती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It is a very huge project.

श्री चतुरानन मिश्र : आप जानते ही हैं। हमारा ख्याल है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई वित्तीय सहायता की व्यवस्था हो, तब ही इन कामों को किया जा सकता हैं। वर्ल्ड बैंक आये, युनाइटेड नेशंस की एजेंसियां आयें, कुछ और लोग आयें तो यह हो सकता है। यह तो पानी का सवाल है।

दूसरा सवाल है कि बिजली के उत्पादन की भी बहुत बड़ी संभावना है। इतनी ज्यादा बिजली जिसका एक बार अध्ययन किया गया था और अभी नेपाल वालों ने जैपानीज विशेषज्ञों के जरिए से करवाया भी है, तो उसकी बहुत बड़ी संभावना है।

इतनी बिजली का उत्पादन करने पर नेपाल उसका खर्चा नहीं कर सकता।

[श्री चतुरानन मिश्र]

मैं अभी पिछले महीने नेपाल गया था, उन लोगों के निमंत्रण पर। आप तो जानते हैं कि अभी एक नई सरकार वहां कायम हुई है।

हमने इसकी चर्चा की थी कि आपके पास तो अरब कंट्रीज को तरह तेल नहीं है और वहां के प्रधान मंत्री ने भी और जो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, श्री गणेश मान सिंह जी, उन्होंने भी कहा कि हम लोगों की तो आर्थिक हालत बहुत खराब है, कैसे हम इसको कर सकते हैं।

उन लोगों से भी और जो वाम-पंथी लोग सरकार में हैं, उनसे भी हमने इस बात की चर्चा की कि आपका एक बहुत बड़ा साधन बिजली बेचने का है। आप बिजली का उत्पादन करें और इसको बेचें। इस मामले में आप भी धनी हो सकते हैं, लेकिन इसका बाजार भारत ही हो सकता है।

चीन वाले चाहे भी, तो नेपाल का बिजली नहीं ले सकते। खूंटा गाड़ते-गाड़ते ही कम से कम बीसवीं शताब्दी खत्म हो जाएगी। इक्कीसवीं शताब्दी में कुछ बात होगी। दूसरे देश भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए भारत को ही देना है।

हमको वहां सूचित किया गया कि उन लोगों ने यह प्रस्ताव किया था कि वे जो बिजली उत्पादित करेंगे, उसमें भारत भी कुछ पूंजी लगाये और कुछ विदेश से भी पूंजी लेंगे। बिजली बिक्री का दर नौ पैसे यूनिट उन्होंने कहा था। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि हम सात पैसे प्रति यूनिट देंगे और सौदा इसी बात पर अड़ा रहा। बात आगे नहीं बढ़ी।

दूसरी बात थी कि आगे क्या होगा, क्योंकि मान लीजिए एक बार हमने कल-कारखाने खड़े कर लिये उनकी बिजली पर और कल को उन्होंने अपना स्विच आफ कर दिया, तब तो हमारे सब कारखाने ठप्प पड़ जायेंगे।

इसलिए पारस्परिक एक विश्वास की भी जरूरत है और गारंटी की भी जरूरत है। फिर अगर बिजली का कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़े, तो कितना रेट बढ़ाया जाएगा? यह सब तै करना है।

मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि यह बात पहले संभव नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पहले जो नेपाल की सरकार थी, वह भारत के प्रति मित्रता की भावना नहीं रख रही थी। मित्रता की बात कहता तो था, लेकिन रख नहीं रहा था। उनकी इस नीति के कारण पहले यह संभव नहीं हो पा रहा था। अब यह संभव है। भारत सरकार इसके लिये फौरन पहल करे। सिंचाई की जो योजनायें हैं उसके बारे में भी नेपाल के लोगों की कुछ भारत से शिकायत है। भारत और नेपाल ने कुछ नदियों में बांध बांधने का तय किया है। भारत ने अपने हिस्से में बांध बांध दिया और एग्रीमेंट के मुताबिक नेपाल के हिस्से में उसी नदी में जो बागमती नदी, अधवारा ग्रुप आफ रिवर्स कहलाती हैं, नेपाल की टेरेटरी में बांध नहीं बांधा। नतीजा यह हुआ कि उनका बड़ा हिस्सा फ्लडेड हो गया। यह उनकी शिकायत थी। उनका यह कहना कहां तक सच है कहां तक नहीं है, यह मैं आपको नहीं बता सकता और भारत सरकार की ओर से कोई इस पर सफाई भी नहीं दी जा रही है। एक और विषय है। पहले की सरकार के साथ अविश्वास का वातावरण था। यह तय हुआ था कि फ्लड की फोरकास्टिंग के लिए 40 स्टेशंज बनाए जायें और वह नेपाल की टैरेटरी में हों। जब बारिश होगी तो उसकी सूचना जल्द मिल सकेगी। मैंने तो यह अनुरोध किया था कि उसको कंप्यूटराइज कर लिया जाए ताकि एक घंटे में ही बिहार में या भारत के लोगों को सूचना मिल सके कि इतना पानी आ रहा है और इतनी बाढ़ आएगी। इससे जान-माल की रक्षा हो सकेगी,

मवेशियों की रक्षा हो सकेगी। काफी रक्षा की जा सकती है। फ्लड प्रोटेक्शन के बारे में एक तो हमारे देश में कंप्यूटर हैं भी कम और है भी तो एक दिल्ली में रखा हुआ है। जैसे दिल्ली में कभी बाढ़ से हम लोग बह जायेंगे? सरकार की नीति है कि कंप्यूटर यहां है अगर बाढ़ वहां आसाम में है बिहार में है। माननीय मंत्री जी ने भी हम बिहार के एम०पी० लोगों को बुलाया था। उस दिन भी उनके यहां बात-चीत चली थी और मैंने कहा था इस बरसात के पहले ही कि वह जो 40 स्टेशंज फ्लड फोरकास्टिंग के लिए बनने वाले हैं उसको शीघ्रातिशीघ्र करा लें। लेकिन इस बार भी नहीं हो सका पहले नेपाल सरकार को शक था कि इसके जरिये भारत गुप्त बातों का पता लगा लेगा। मैंने तब वहां जा कर इस बार इसकी चर्चा की पोलिटिकल पार्टीज के नेताओं से क्योंकि सरकार नई बनी है तो पता चला कि वे लोग जानते भी नहीं हैं उन लोगों ने कहा कि उनके पास तो इसकी सूचना नहीं है। किसी ने नया एप्राच किया ही नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। हमारी तरफ से नेपाल के साथ एक बराबरी का संबंध हो बात-चीत मित्रता की होती है लेकिन इसमें भी हमको अभाव लग रहा है। खटक रहा है कि यह क्यों बात-चीत नहीं की जा रही है? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक अनुकूल परिस्थिति आई है, जो पिछली नेपाल सरकार के वक्त में नहीं थी। संयोग से आपके समय में वह नई स्थिति उत्पन्न हुई है। एक दिन प्रश्नोत्तरकाल में मंत्री जी ने कहा भी था, आश्वासन दिया था कि जल्द ही वह स्वयं नेपाल जायंगे और वहां की सरकार से बात चीत करके इसका समाधान करेंगे यह तो अच्छी बात है जो कहा था और उसमें कहा था और उसमें भी होगा। लेकिन यह तो बाढ़ के बारे में होगा, बिजली के बारे में यह नहीं हो सकेगा।

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) डैम के बारे में।

श्री चतुरानन मिश्र: डैम के साथने हाइडल पावर यह आपका विभाग तो नहीं है इसीलिए हमने कहा। बिजली विभाग ने यह नहीं किया। बिजली मंत्री को भी जा कर उसके बारे में प्रयास करना होगा। नेपाल में नई सरकार के बनने के बाद बिजली मंत्री के पास भी, प्रधान मंत्री जी के पास और विदेश मंत्री जी के पास भी इस सम्बन्ध में कई बार पत्र लिखे। मेरा अपना ख्याल है कि नेपाल और भारत का लांग टर्म इकोनोमिक अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारी दोस्ती स्थायी रूप धारण कर लेगी। अभी माननीय सदस्य जाधव जी ने कहा कि अगर गंगा से पानी चला जाए कावेरी तक ही तो भारत की राष्ट्रीय एकता में बड़ी मदद होगी। उसी तरह से अगर लांग टर्म इकोनोमिक अरेंजमेंट नेपाल के साथ हो तो वह भी दृढ़ मित्रता का आधार होगा क्योंकि हम एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते।

[श्री चतुरानन मिश्र]

इसलिए मैं ज्यादा भाषण नहीं दे करके मंत्री जी से फिर एक बार यही अनुरोध करूंगा कि कम से कम अपने विभाग की ओर से वह शीघ्रातिशीघ्र करें। नेपाल में वामपंथी लोग भी सरकार में हैं और हम लोगों की भी मदद की जरूरत हो हम लोग बहुत यातना सहते हैं, तो हम लोग भी करेंगे। कि इस काम को जल्दी से किया जाय। अगर यह शुरू हो जाय तो फिर चलेगा और इसमें काफी समय लगेगा। कोई यह नहीं कहेगा कि इसको आप तुरन्त कर दीजिये यही मेरा अनुरोध है। इस नयी परिस्थिति के अनुसार, सरकार जल्द-से-जल्द कदम उठाये, चूके नहीं। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता था। धन्यवाद।

डा० अब्दार अहमद खान (राजस्थान): उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती कमला सिन्हा जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

वास्तव में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जिस पानी के लिये हम तरसते हैं, जिस वर्षा के लिये हम तरसते हैं, उस वर्षा का इतना कीमती पानी बाढ़ की शक्ल में हमें बरबाद करता हुआ बेकार चला जाय, वाकयी यह चिंता का विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, जब भी बाढ़ आती है तो उससे जो बरबादी होती है, उसके शिकार गरीब तबके के लोग होते हैं, मजदूर तबके के लोग होते हैं, किसान तबके के लोग होते हैं, बाढ़ से कभी अमीर लोग प्रभावित नहीं होते। जो शहरों में बंगलों के अन्दर रहते हैं या बड़े-बड़े मकानों में रहते हैं, वे प्रभावित नहीं होते। बाढ़ से खासतौर से उन किसानों की बरबादी होती है जिनके खेत के खेत उस बाढ़ के पानी से कट जाते हैं और खेत खेती करने लायक नहीं रहते हैं। बाढ़ उन कृषि मजदूरों को लाचार करती है जो ी खेतों में काम करते हैं। बाढ़ के पानी से झुग्गी-झोंपड़ियों के या गांव के अन्दर बसने वाले लोग बरबाद होते हैं। तो बाढ़ जो प्रभावित होते हैं, वे गरीब और किसान तबके के लोग होते हैं और खास तौर से गांवों में और झोंपड़ियों में रहने वाले लोग होते हैं। तो इस पर नियंत्रण पाने और इसके लिये एक स्थायी उपाय करना नितांत आवश्यक है। जैसा कि अभी चतुरानन जी कह रहे थे कि बिहार के अन्दर जो बाढ़ आती है, नेपाल से जिस प्रकार से बाढ़ का पानी आता है, उसका घर में सोते हुये लोगों को, काम करते हुये लोगों को पता नहीं होता। एकदम जिस प्रकार से पानी आता है, उसमें लोग बह जाते हैं, बरबाद हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन साधनों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब भी नेपाल में बहुत ज्यादा पानी बरसे और उस बाढ़ का पानी बिहार के अन्दर आने वाला हो और अगर उसकी पहले से सूचना हो जाय तो हम पशुओं की हानि को बचा सकते हैं, मनुष्यों की हानि को बचा सकते हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे प्राथमिकता के रूप में उन साधनों को मजबूत करने पर विचार करें और उन कम्युनिकेशन साधनों का उपयोग स्थायी रूप से कर सकें। जब भी एक जगह बहुत पानी बरसे और उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्र पर आने वाला हो तो दूसरी जगह से आदमियों को हटाया जाना चाहिये, पशुओं को हटाया जाना चाहिये। हम किसी भूमि को या खेत को तो नहीं हटा सकते हैं लेकिन जन-हानि को कम से कम कर सकते हैं, पशु-हानि को कम से कम कर सकते हैं।

दूसरे, आज देश के अन्दर पेट्रोल का संकट चल रहा है। इस पेट्रोल और तेल के संकट की अगर विश्व में कोई चीज सब्स्टीट्यूट हो सकती है, तो हम मानकर चलते हैं कि वह बिजली ही होगी। वह धीरे-धीरे पेट्रोल और डीजल जैसे साधनों की कमी की पूर्ति कर सकती है या इसके सब्स्टीट्यूट के रूप में काम आ सकती है। तो जो हमारे पास पानी उपलब्ध है, चाहे वह नेपाल से चलकर बिहार में आता हो, उसको

हम प्राथमिकता के रुप में देखें और जगह-जगह उसे रोककर बिजली पैदा करें । इसके दूरगामी प्रभाव को हम देख सकते हैं और भविष्य में आने वाले संकट से बच सकते हैं। बेशक पानी तो है, लेकिन उसका सदुपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। वह हमें करना चाहिये।

इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी का विशेष ध्यान राजस्थान की परिस्थिति की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं । राजस्थान से संबंध रखता हूं । राजस्थान एक बहुत दुर्भाग्य पूर्ण प्रदेश है जो या तो अकाल से ग्रसित रहता है या बाढ़ से ग्रसित रहता है या बाढ़ और अकाल दोनों से ग्रसित रहता है। महोदय, अभी गत कई वर्षों से पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ रहा था । उस कारण लोग मर रहे थे । महोदय, अभी वर्ष 87 में भी इस प्रकार का अकाल पड़ चुका है जोकि पिछले सौ वर्षों का सबसे भयंकर अकाल था तो उस समय उस समय के प्रधानमंत्री राजीव जी खुद वहां गए, 840 करोड़ रुपया दिया और धानी-धानी गांव-गांव जाकर किसी आदमी को मरने नहीं दिया वहां चारा पहुंचवाया, अनाज पहुंचवाया और लोग बच गए । लेकिन, दुर्भाग्य से इसी वर्ष उसी पश्चिमी राजस्थान में इतनी भयंकर बाढ़ आई, इतनी भीषण बाढ़ आई मैं देख रहा था अपने पीछे, मेरे पीछे गजसिंह जी बैठते हैं, जो जोधपुर के ही रहने वाले हैं, वे भी वहां थे, लेकिन इस वक्त यहां नहीं हैं, हमने देखा उस पश्चिमी राजस्थान में, जहां लोग पानी के लिए तरसते थे, वहां बाढ़ में 200 से ज्यादा लोग मर गए, हजारों लोग बेघर हो गए, लाखों पशु मर गए और भेड़ें जो वहां बहुत होती हैं, उनसे खेत के खेत सफ़ेद इस तरह से रंग गए कि कोई कह नहीं सकता था कि यहां ऊन पड़ी है या मरी हुई भेड़ें पड़ी हैं। तो इस प्रकार की वहां बाढ़ आई । मैंने अपने एक स्पेशल मेंशन में भी पहले यहां मेंशन किया था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इस प्रकार से भगवान की ओर, आसमान की ओर देखते थे । मैं आपको बताऊं कि एक पेड़ पर सुबह 4 बजे 62 आदमी चढ़े और दिन के 11 बजे तक आकाश की ओर देखते रहे कि शायद कोई हमें आकर बचाए, कोई हेलीकाप्टर आकर बचाए, लेकिन कोई बचाने नहीं आया और दिन के 11 बजे वह पेड़ गिरा, जिससे उसमें से 32 आदमी मर गए। इस तरह की वहां कई घटनाएं हुई। वहां इतनी बड़ी जन-हानि हुई, इतनी बड़ी धन-हानि हुई कि कभी जिनके खेतों की कीमत लाखों रुपए होती थी, आज वहां अगर जाकर देखें तो पाएंगे कि पचास-पचास गज नीचे, बीस-बीस गज नीचे खाइयां बन गई हैं, किसी प्रकार की भूमि नहीं रही है । जो लोग कल तक लखपति थे, आज खाकपति हो गए हैं ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इस समस्या की ओर तत्काल ध्यान दें, चाहे वह बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्यप्रदेश में हो, कहा भी हो मैं खाली यह नहीं कहना चाहता कि मैं राजस्थान से हूं तो राजस्थान की आप सहायता करें, लेकिन जहां भी इस प्रकार से आदमी लखपति की हैसियत से सोया हो और सुबह कंगाल रहा हो, खाने के लिए, कुछ पाने के लिए हैलीकाप्टर की तरफ़ देखता हो कि अगर कोई थैली गिरे तो अपना पेट भरे, उनके लिए केन्द्र सरकार की प्राथमिकता के आधार पर तत्काल सहायता होनी चाहिए और जो लोग मर गए हैं, उनके परिजनों को एक ठीकठाक राशि, जिससे उन्हें सांत्वना मिल सके, मिलनी चाहिए । मैं राजस्थान के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि 200 से ज्यादा लोग मर गए, लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ़ से मरने वालों को एक पैसा नहीं दिया गया, जबकि और जगह साइक्लोन आया, वहां सब कुछ दिया गया । राजस्थान में राज्य-सरकार ने पांच-पांच सौ रुपए दिए हैं। महोदय, आप देख सकते हैं कि पांच सौ रुपए से क्या होता है ? जिनके घर गिर गए, जो बर्बाद हो गए, उनको पांच-पांच सौ रुपए दिए और बाद में ढाई-ढाई सौ

[डा० अब्दुल अहमद खान]

रुपए और बढ़ा दिए तो क्या साढ़े सात सौ रुपए में कोई मकान बनता है ? मेरा आपसे आग्रह है कि उन लोगों के लिए कोई ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए, सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए, जिनके मकान गिर गए हैं और ऐसी व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिये जिससे उनके रिहेबलीटेशन का काम हो सके । मैं मानता हूं कि लोगों का जितना नुकसान होता है उसकी पूर्णरूप से तो पूर्ति नहीं हो सकती लेकिन कम से कम इतनी पूर्ति जरूर की जानी चाहिये जिससे वे दुबारा अपनी पाजीविका कमाने योग्य हो जाए, उनके परिवार को एक सांत्वना मिल जाए, वे समाज के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर सकें । मैं मानता हूं, वह आदमी समाज के अंदर वापस अपना स्थान तो नहीं पा सकता जिसके पास मान लीजिए 100 बीघा या 20 बीघा या 10 बीघा अच्छा खेत था और वह बेकार हो गया लेकिन कम से कम वह दो जून की रोटी कमा सके इसकी व्यवस्था तो सरकार कर दे । बाढ़ में नुकसान हुआ यह उसका तो दोष नहीं होता भगवान का दी हुई सजा होती है । मैं बार-बार यह कहता आया हूं वहां भी और पब्लिक प्लेटफार्म पर भी कि जब भगवान किसी बात की सजा देता है तो हम प्रकृति से संघर्ष नहीं कर सकते भगवान से संघर्ष नहीं कर सकते उसकी सजा को दूर नहीं कर सकते लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं कि उस सजायाफ्ता आदमी को जिसको बाढ़ या अकाल या किसी प्राकृतिक प्रकोप से सजा मिली है उसको कम से कम दो जून की रोटी मिल सके उसके सिर पर साए की व्यवस्था कर सकें समाज के अंदर दुबारा से रह सके इसकी व्यवस्था हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जहां भी बाढ़ से तबाही होती है वहां पूरी मदद दें और जैसा मैंने अभी राजस्थान के बारे में जिक्र किया कि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद केन्द्र सरकार ने वहां कोई मदद नहीं दी। इस बारे में मैंने एक सवाल पूछा था और एक पत्र भी लिखा था जिसका मुझे जवाब मिला कि नाइन्थ वित्त-कमीशन ने हर राज्य का पैसा पांच साल के लिए निर्धारित कर दिया है और राजस्थान के लिए भी 625 करोड़ रुपया निर्धारित है हर साल उसमें से 1/5 हिस्सा राजस्थान सरकार ले सकती है । यह 75 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार देती है और 25 परसेंट राज्य-सरकार देती है इससे तो मैं पूर्णतः सहमत हूं लेकिन जब इस प्रकार की कोई विपदा आ जाय और मान लीजिए राज्य सरकार 25 प्रतिशत कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है या ऐसी स्थिति में नहीं है तो उस समय केन्द्र सरकार जो 75 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन देती है उसके लिए वह कंडीशन न रखे कि जब तक राज्य सरकार 25 प्रतिशत योगदान न दे तब तक ....

तब तक हम उस 75 प्रतिशत को भी रिलीज न करेंगे । अगर ऐसी कंडीशन लगा दी तो आज मैं मानकर चलता हूं कि बहुत सी राज्य सरकारों की ऐसी स्थिति है कि वह 30 या 35 करोड़ रुपया भी किसी प्राकृतिक विपदा पर खर्च नहीं कर सकती है । तो उस समय जो लोग विपदा से परेशान है, वे मुंह ताकते रह जाते हैं । तो ऐसी प्राकृतिक विपदाओं में जो यह पैसा केन्द्रीय सरकार ने 9वें वित्त आयोग के तहत रखा है उसी अंदर 25 परसेंट जकी कंडीशन नहज्र रहनी चाहिए क्योंकि वह इम्मिजयेट रिलीफ़ देने वाली बात होती है । अगर 25 प्रतिशत राज्य सरकार के अंशदान के आधार पर केन्द्र सरकार देखती रह गई तो राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार आपस में बातचीत करती रहेंगी वह बाढ़ग्रस्त किसान, वह बाढ़ग्रस्त मजदूर, वह बाढ़ग्रस्त आदमी, जिसका मकान गिर गया है, उसको राहत नहीं मिल पाएगी तो ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार बिना 25 या 75 परसेंट का राग अलापे जो भी राज्य सरकार की राशि बनती है, वह दे और उसके अलावा जो भी

और दे सकती हो उसकी मदद करे ताकि इस देश के बाढ़ग्रस्त निवासी को यह महसूस हो कि हां इस देश के अंदर सरकार है, हां इस देश के अंदर हमें देखने वाला कोई है, हां इस देश के अंदर हमारी समस्या से जूझने वाला कोई है ।

मैं आपके माध्यम से अंत में सरकार से पुनः यह आग्रह करूंगा कि जो भी बाढ़ से प्रभावित लोग हैं और इस वर्ष जो भी हुए हैं, उन्हें वह पूर्ण रूप से एक विस्तृत जानकारी लेकर के राहत पहुंचाए जिससे कि वे तसल्ली की सांस ले सके । धन्यवाद ।

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh): Respected Vice-Chairman, Sir, there are some areas in the country which are often affected by severe, terrible, terrific drought. There are some areas in the country which are often affected by devastating floods resulting in human deaths, cattle deaths and devastating damage to bridges, buildings, crops, land etc. There are lakhs of villages which are suffering from drinking water problem. This is the scenario in our sacred motherland after 43 years of independence. What a pitiable condition it is? Sir, as a medical doctor I can compare drought with T.B. and floods with cholera or gastroenteritis. T.B. kills the patient not suddenly but after long time, but cholera kills the patient immediately. So, drought is like T.B. and floods like cholera. The treatment for cholera and T.B. is different, but the floods and the drought can be controlled with the same medicine, with one single medicine, with one stroke both the birds can be hit. By controlling floods drought can automatically be controled.

Sir, this flood situation is not confined to Bihar only. It is everywhere in the country. There are some States, like Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Madhya Pradesh, which are even at the present moment under the grip of floods. Flood situation is very common in Andhra Pradesh. The Godawari, not one but twice or thrice in a year, is under the grip of floods. So, everywhere in this country this is a serious phenomenon. Every time, in every Session we discuss this subject in the Parliament. The Members of Parliament give various suggestions. They will take the Government to task and the Government will shed crocodile tears. It may be any Government. Afterwards it forgets and the floods and drought are repeatedly taking place every year. I am doubtful whether the Gotvernment is considering this as an indirect way of controlling population explosion. Already the Government has forgotten the ordinary methods of population control.

They may be thinking of encouraging this indirect method. Even when they take measures, they are only temporary methods. They are not taking permanent measures. They are not very serious about taking permanent measures. My stress is on permanent measures. I would like to suggest some of the measures to be taken on a permanent basis.

(i) Construction of major, medium and minor irrigation projects on the rivers. These projects will control floods. Not only that, they will provide irrigation, power supply, drinking water supply, navigational facilities etc.

(ii) Delay in clearance of projects should be avoided. There are so many projects. For example, from Andhra Pradesh, about 10 major and 20 medium projects have been sent by the State Government to the Central Government for clearance. These are still awaiting approval. There is undue delay in giving clearance to such projects. This should be avoided.

(iii) There should be adequate allocation of funds for flood control measures.

(iv) The drainage system should be improved. A very serious problem in Andhra Pradesh is the drainage system. It should be improved.

(v) Desilting of the existing projects should be done.

(vi) A more active and positive role should be played by the Central Government in solving inter-State water disputes.

[Dr. Narreddy Thulasi Reddy]

The best example is that of Telugu Ganga Project. The Centre is not at all taking any interest in it. So the problem is continuing.

Next I come to the garland canal. This plan was proposed by Mr. Dinshaw Dastur. It envisages a Himalayan canal surrounding the southern line of the Himalayan region. There is a central canal and there will be a southern garland canal encircling the Indian peninsula. It involves construction of 11,000 kilometres long canals with over 300 integrated lakes. It will provide irrigation to all parts of the country. It will prevent droughts and floods, generate unlimited hydel power, provide a water course for steamers and give jobs to lakhs of people. In the year 1977, the then Prime Minister announced that the proposal for this canal was under consideration. Afterwards, Government has not taken any decision on this. It will hit many birds with one stone. It will check the Himalayan snow-line from receding. The world-renowned Engineer, Mr. Buckminster Fuller, has commended this proposal. I would request the Government to examine this proposal sincerely and seriously.

The next proposal is what has already been suggested by so many Members—i.e. Dr. K. L. Rao's proposal of inter-linking Indian rivers. It involves linking of Brahmputra to Ganga, Ganga to Godavari, Godavari to Krishna and Krishna to Cauvery. This suggestion may also be considered.

Regarding Andhra Pradesh, because I hail from Andhra Pradesh, I would like to stress one point. Floods in Godavari is a common phenomenon. To prevent such floods, the only solution is to construct the Pollavaram project. Nearly 15 years back, the Government of Andhra Pradesh sent a proposal regarding the Pollavaram project to the Government of India. Afterwards so many reminders have been given. But so far no action has been taken, no decision has been taken regarding this project. Once again, I request the Government of India to examine this project. If you want any clarifications, you ask us. But you take the initiative.

With these few suggestions, I conclude my speech by supporting the Resolution moved by Smt. Kamla Sinha. Sir, I thank you, once again, for giving me this opportunity.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Sir, the question of floods in Bihar which has legitimately engaged the attention of the House and the country, is not confined to Bihar alone. As a matter of fact, as pointed out by the learned speakers here, the question is of floods which ravage various parts of India over and over again. This question is also linked with the paucity of water in certain regious of India, and we have to find a solution to this. The solution to the problem of floods lies in finding out the causes which have led to floods in the various regions of India, particularly, Bihar.

One of the main reasons is that indiscriminate deforestation in the higher reaches of the Himalayas has rendered most of our mountains naked, resulting in fast flow of water into the plains and also erosion of earth from the higher reaches, with the result that the riverbeds are silted, though much of the earth is washed out into the sea also. One of the remedial measures is that we should resort to afforestation in the higher reaches so that erosion of earth from the Himalayas is arrested and thus settling of earth in the riverbeds is diminished. And whatever earth has got deposited in the riverbeds should be dredged so that water can flow freely, without inundating the areas adjoining the rivers. But afforestation is gentrally resorted to in the plains and not on the high mountains. I would therefore, suggest to the Government that the programme of afforestation aided by the World Bank, known as Social Forestry, should be confined more to the higher reaches so that erosion of earth from those areas is lessened and the floods will not be so fast and there are no flash floods, which cause greater loss than floods which come slowly.

Secondly, there has to be a long-range solution to this problem, and that can be obtained by the grand scheme as envisaged by our planners with regard to a link system among the various rivers of India so that when there are floods in certain rivers, that water can be diverted into other lines which are not flooded or to those areas which are not flooded, and that water can be dammed and kept in reservoirs and used for purposes of generating electricity, irrigation and similar other purposes.

Sir, it is because of our inability and incompetence that we have not been able to harness our rivers and have not been able to make proper use of this natural wealth. Whereas on the one hand certain areas in our country are suffering for want of water—as pointed out by the honourable speaker from Saurashtra who said that in that area people and cattle have to suffer and die because there is no water—on the other there are certain areas where there is too much water and people have to suffer and die because of too much water. I would, therefore, stress that a long-range programme whereby the river waters in the country can be harnessed and used for the betterment of the country should be envisaged. Large tracts of land in our country are not irrigated. Their irrigation can also be possible if these waters are properly harnessed and properly used. We can learn from other countries also. For instance, in European countries floods are not so common as they are in our country, the reason being that those countries have over a time been able to harness their rivers to see that flood waters do not go so far as to damage the very life of the people, as to cause loss to the country. We can send our delegations from the relevant Ministries to those countries which have had the experience of controlling floods, and from that we can learn.

So far as the State of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab are concerned, there are five important rivers flowing through these States. But the water from those rivers also often floods those areas. Construction of dams has been done in those areas, but no profit has come to those States from that construction, the reason being that whatever electricity is generated, it is taken away by the Central Government and no gain comes to these States. In future what should be done is that when we embark upon a programme to control floods and to generate electricity from the waters which are flowing in various rivers, we should give to the States assistance to construct those projects so that those are their projects and whatever electricity they produce, is used for the welfare of those States by sale of that electricity and it is not taken away by the Centre alone and those States are not left high and dry as has happened in Jammu and Kashmir.

Moreover, a very valuable suggestion has been made by Mr. Chaturanan Mishra with regard to Nepal. It is worthy of consideration. Very important rivers originate from Nepal, particularly the Brahmaputra which floods Bengal and some other areas of our country. Some arrangement with the State from which the water comes, is the need of the time as we have done with Pakistan. We have had the Indus Water Treaty. Our water flows into Pakistan. But the waters of Nepal flow into India. Therefore, an arrangement with that country whereby the waters flowing in the rivers can be properly distributed, is necessary.

Moreover, among the States in our country in our country there is quarrel with regard to distribution of water. Even today Punjab says that some of its water is being wrongly taken by other States. Such quarrels should be settled by the Central Government so that in future when we make any dams, they do not become a source of trouble for us, a source of bickering or a source of quarrel among various States. So, what is needed today is that we should do all things necessary to see that floods do not ravage our country. For that we should resort to dredging, aforestation and secondly we should take such long range measures whereby we link the rivers of India by a garland scheme as pointed by some of our speakers here. But that would need funds, very very huge funds for which international help will be needed. All those measures will have to be con-

[Shri Shabbir Ahmad Salaria]

sidered carefully and deeply and with great gravity with which we are faced so that a solution can be found to this problem which has been existing in our country for long.

Thank you very much.

श्री अन तराम देवशंकर दवे (गुजरात) उपसभाध्यक्ष महोदय, कमला सिन्हा जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। क्योंकि इसी सदन में देश के विभिन्न प्रदेशों से आये हुए सांसदों ने अपने-अपने विचार यहां पर रखे। अभी सलारिया जी ने अपने कश्मीर के बारे में जिक्र किया, मिश्र जी ने भी कुछ सुझाव दिये। इस सदन में और बहुत से लोगों ने सुझाव रखे। महाराष्ट्र के सांसद ने अपने यहां की बात रखी राजस्थान की बात हुई मैं भी अपने गुजरात की बात यहाँ रखना चाहता हूं।

इस प्रस्ताव में बिहार, नेपाल और मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के बारे में जो चीज कही गयी है उसको किसी तरह से रोका जाना चाहिए। जहां बहुत पानी है वहां भी समस्या है जहां पानी नहीं है वहां भी समस्या है। थोडे दिन पहले सौराष्ट्र में बारिश हो गयी तो वहां की स्थिति बहुत खराब थी वह अच्छी हो गयी। कच्छ में पानी गिरा नहीं गिरा तो बहुत कम गिरा लेकिन जहां पानी गिरा है वहां की हालत भी खराब है। इस बारे में जो बडे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, डैम योजनाए बन रही है में सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। गुजरात में बडी योजना बन रही है नर्मदा प्रोजेक्ट की, सरादार सरोवर का काम अभी चालू है कई वर्षों से। सरदार पटेल ने 1944 में यह कहा था कि यह जो पानी जा रहा है नर्मदा से और बाढ़ जो आयी है इससे खेतों को नुकसान हुआ है, किसानों को नुकसान हुआ है। करोड़ों रुपये का नुकसान आज दिन तक हुआ है इसको रोका जाना चाहिए। यह जो योजना बनी है इस पर 900 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट की क्लीयरेंस भी दे दी है। हमारी यह मोर्चा सरकार बड़ी जोर से इस काम के पीछे पड़ी हुई है इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं लेकिन एक खतरा है। अभी-अभी पर्यावरणवादियों ने उस योजना में दखल देने का प्रयास शुरू किया हुआ है। मैं समझता हूं उन लोगों को आज दिन तक पता नहीं है कि जहां बारिश नहीं गिरती है वहां यह पानी जायेगा इस नर्मदा का पानी कच्छ तक जायेगा। जहां आज भी लोग दो-दो किलोमीटर से, तीन-तीन किलोमीटर से, चार-चार किलोमीटर से पानी भर कर लाते हैं। वहां यह पानी जाने वाला है। इस तरह की मुश्किलात खड़ी कर दी जायेंगी तो यह योजना रुक जायेगी और मैं समझता हूं इससे बड़ा भारी नुकसान देशभर में होगा। इस योजना से सिर्फ गुजरात को फायदा मिलना है ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश को बिजली मिलेगी, राजस्थान को पानी मिलेगा, महाराष्ट्र को बिजली मिलेगी। मध्य प्रदेश में बिजली मिलने से बड़े-बड़े उद्योग आगे आयेंगे। महाराष्ट्र में बिजली मिलने से काफी उद्योग आगे आयेंगे। गुजरात में पानी मिलने से जहां सूखा पड़ता है और सरकार का करोड़ों रुपये का नुकसान होता है, उनको लाभ पहुंचेगा। जब उनको पानी मिलेगा तो पैसा हमारा बच जायेगा, फसलें अच्छी होंगी, नये पेड़ लगेंगे। पड़ों के नाम पर पर्यावरणवादी जो अपना आंदोलन चला रहे हैं उनको पीछे हटना पड़ेगा। मैंने अभी सुना, महाराष्ट्र के सदस्य कह रहे थे, वह भी किसान हैं, यह जो नर्मदा योजना चल रही है उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। मैं कहना चाहता चाहूंगा कि कमला सिन्हा जी जब अपनी बात पूरी करें तो उस समय इस बात पर जोर दें कि गुजरात में जो यह योजना चल रही है यह पूरी हो कर रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कहा है कि यह योजना पूरी होनी चाहिए जिससे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यानी सभी प्रदेशों को बड़ी मात्रा में फायदा हो। दूसरी बात मैं यह कहने जा रहा हूं कि वाटर ग्रिड हमारे देश में बनना चाहिए। क्योंकि इस योजना की हमारे देश में बहुत आवश्यकता है। अभी बंगाल के सदस्य ने जो बात बताई है, उसका मैं

पूरा समर्थन करता हूं । अभी हमारे देश में पैट्रोल की कमी महसूस की जा रही है । लेकिन अगर वाटर ग्रिड की योजना हमारे देश में बन जाएगी तो उससे सारे देश को लाभ हो सकता है । माननीय मंत्री महोदय से मैं विनती करूंगा कि वे इसका सर्वे करवायें और देखें कि इसमें कितना खर्च आएगा, कितना पैसा लगेगा और कितने सालों में यह योजना बन सकेगी और कहां से हमें पैसा इक्ट्ठा करना होगा, या वर्ल्ड बैंक के पास जाना होगा । नेशनल मोर्चे की सरकार अभी आई है और एक के बाद एक कदम आम लोगों के लिए उठा रही है । ऐसे मौके पर इस प्रकार की योजना बनाकर देश के सामने उसको रखनी चाहिए । इस समय हम जो पेट्रोल की कमी महसूस कर रहे हैं, अगर ग्रिड बन जाय तो पेट्रोल की कमी भी हमें कम महसूस होगी और देश को फायदा होगा । हमारे जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उसमें हम ग्रिड योजना के अन्तर्गत एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे । इसलिए यह भी विनती करूंगा कि इन सब बातों का सर्वे किया जाना चाहिए । मैं फिर श्रीमती कमला सिन्हा जी को इस प्रस्ताव के लाने के लिए उनका समर्थन करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now the Minister will reply.

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI MANUBHAI KOTADIA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very thankful to the hon. Member, Shrimati Kamla Sinhaji who has brought forward this Resolution before the House concerning such an important matter of national interest. This has provided me an opportunity to go into this matter in great depth and great detail. I am also thankful to the hon. Members who have participated in the debate and made valuable suggestions.

Sir, in her Resolution she drew the attention to the grave situation arising out of the recurring floods in North and Central Bihar. The hon. Member has emphasised the urgent need for taking effective remedial measures in this regard. I fully share the concern expressed by all the Members. During the discussion, hon. Members also referred to several connected issues like strengthening of embankments, taking proper measures for prevention of erosion, strictly enforcing laws against cutting trees and implementing recommendations of the Rashtriya Barh Ayog and implementing Garland System Canal, providing crop insurance to protect farmers' interests, for desilting and dredging operations, emphasis was also on advanced flood forecasting and warning system. I am happy to note that several Members have realised that control of floods in North Bihar is very much dependent on the cooperation of Nepal and also suggested speedy resumption of negotiations and agreements in this regard. Sir, we realise the importance of water management and have given due position to this in our Action Plans. We firmly believe that the stability of our national life is totally linked to the stability of our water systems. Due importance has been given to ensure long-term water stability through harnessing rain water on the catchment areas, thereby *inter-alia* effectively controlling floods.

The State of Bihar has a geographical area of 17.4 million hectares, that is, 5.29 per cent of the total Geographical area of the country. The flood prone area in Bihar as assessed by Rashtriya Barh Ayog in March, 1980 was 4.26 million hectares, that is, 24.5 per cent of the geographical area of the State...and 12.3 per cent of the total flood prone area of the country. Looking to the average for the period 1953 to 1988, the population affected by floods in Bihar is 6.66 million every year, that is 20.58 per cent of the total flood affected population of the country. During 1990 monsoon, so far 15 districts have been declared flood affected by the State Government of Bihar. During this year, a total area of 5.07 lakh hectares and a population of 27.63 lakh and about 3,000 houses have been affected by floods. As reported by the State Government of Bihar, large and extensive flood management works,

[Shri Manubhai Kotadia]

such as, the embankments, channel improvement and town protection works, in Bihar have provided protection to about 2.92 million hectares of area, that is, 68 per cent of the total flood prone area of the State and an amount of Rs. 500 crores has been spent upto March, 1990. The State's plan outlay for the year 1990-91 is Rs. 40 crores.

The construction of barrages on the rivers and embankments along the length of the major rivers in the flood prone area has confined the rivers and checked their vagrant migration. Kosi and Gandak are good examples of projects constructed with cooperation of Nepal in this regard. The river Kosi which used to migrate over large stretches is now confined within 7 to 8 kms. between the embankments. These works have also resulted in increased kharif cultivation and provided free, uninterrupted surface communication.

As I already mentioned, the widespread misery caused by recurring flood has been a matter of concern to all of us and Ganga Flood Control Commission was set up for preparing the plans for tackling the floods in the Ganga Basin. The entire Ganga subbasin was divided into 23 river systems. The Ganga Flood Control Commission has already prepared comprehensive plans of flood management for all the river subbasins of Bihar in which both sort term and long term measures have been outlined. These include construction of reservoirs, embankments, anti-erosion works, drainage channels and town protection works, etc. These plans have been sent to the State Government for carrying out detailed investigations with a view to formulate the specific schemes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That is the complaint of many hon. Members. The hon. Minister will not that you are carrying on this paper work but floods are going on. (*Interruption*). That is what the conplaint is.

SHRI MANUBHAI KOTADIA: I will come to that point later on. We have taken up with Nepal the proposal for constructing Kosi high dam at Barakshetra located in Nepal territory. A project report was also given by us to the Government of Nepal in 1981. But uptil now, there is no response. This dam, when constructed with the cooperation of Nepal, will protect lrage areas in Bihar from flooding. Besides Kosi high dam, proposals for constructing storage dams on river Kamla, Bagmati and Kankai and others have also been discussed. But even with these dams, flood situation in North Bihar will not get mitigated to the extent people of Bihar would expect. We have also taken up the issues regarding tying up and extension of river embankments at the border into Nepal territory and some cases have been agreed to by HMG Nepal in the official level meeting held with them during May 1990. Actions on these will be pursued further after the monsoon season. *During the recent visit of the Nepalese* Prime Minister to India in June 1990, the two Prime Ministers declared their intention of cooperation and made a specific mention of the need for harnessing of the waters of the common rivers for the benefit of the people. Sir, a total 4.00 $.M network of 36 flood forecasting stations has been set up by the Central Water Commission in Bihar covering all the major rivers causing flood and these are providing ferecasts to help in mitigating the flood damages. By now, about 400 flood forecasts have been issued in North Bihar as against 1000 flood forecasts issued last year. Sir, for the entire state of Bihar, during this year, about 700 flood forecasts have been issued against 1290 last year. These flood forecasts have been helping the State in taking appropriate advance action for the safety of the people. As many of the rivers flowing through Bihar have their origin in Nepal, it is necessary to extend effective forecasting activities with the cooperation of Nepal. The Government of Nepal had agreed in December 1987, in principle, for setting up hydrometeorological stations in Nepal. About 45 stations have been identified by us to be set up in two phases. Fifteen stations were programmed to be made operational before the 1989 monsoon and others subsequently. However, these could not be done so far as there was no response from Nepal We have been continuously pursuing the matter. We again requested them for

the expeditious implementation of the scheme during the Indo-Nepal Sub-Commission of Water Resources meeting held at Kathmandu in December, 1988. We have also reminded the Government of Nepal during July 1989, December 1989, May 1990, July 1990 and August 1990. I would like to mention that I have also requested the hon. Minister of External Affairs to take up the matter with the Government of Nepal for expeditious settlement as I assured in my reply to a Rajya Sabha question on 9th August, 1990 by the same hon. Smt. Kamla Sinhaji. I will also take up the matter with the Government of Nepal and if necessary, I will also visit Nepal as early as possible to finalise the issues and come to an agreement. Sir, here I would like to mention about the Technology Mission to which some hon. Members made a reference. In the approach paper for the Technology Mission set up in 1987, stress was laid on the non-structural measures to give quick physical relief to the chronically affected population by floods. These items had not received enough attention in the past as compared to the traditional activities However, the State Government still insisted on investments only in traditional measure like construction of dams, embankments, drainage channels, etc. Owing to this divergence of approach and views of the State Government, no progress would be made with the technology mission. It has remained, all the while, an idea.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You have to come out with new ideas. The new Government is there New ideas can come.

SHRI MANUBHAI KOTADIA: In the light of the experience gathered over the years, our approach will now onwards be on an appropriate mix of different measures for flood management so as to ensure a reasonable degree of protection from flood losses at economic costs and at the same time, to ensure that life under flood conditions does not get handicapped by disruption of civic amenities. To the extent physically and economically possible, we may reduce flood spread by removing drainage congestion, by increasing channel capacity or by storing flood waters. In plains, like that of North Bihar, absolute flood-free areas are bound to be limited. Hence measures to make the areas flood-proof are likely to be more workable and effective. Hon. Members will appreciate we will have to resort to and provide for measures like building raised platforms, assured communicaion, drinking water supplies etc. It is in this direction that a substantial assistance programme for the flood-proofing measures in the chronic flood-prone areas is proposed to be included in the Eighth Plan. To begin with, a token provision of about 9 crores already stands included in the Ministry's budget for this year. Details of the specific schemes to be supported under this programme are now to be worked out in consultation with the States.

Hon. Member, Kamlaji, desired to know the status of Mokamah Tal Drainage Scheme. I may mention that the plans for Mokamah Tal Drainage Scheme have been drawn by the State Government to take up the work in stages. First stage works have been completed and second and third stage works are in progress. Incomplete schemes have been included in the Eighth Plan.

She has also made a plea that the funds required by the Government of Bihar for the drainage schemes in Kosi and Gandak commands should be made available to the State by the Centre.

Sir, as per the present policy, irrigation and flood management projects are planned, investigated, executed and funded by the State Governments from their own resources. The Central Government gives block grants and loans, not attached to any particular project or sector of development. Thus, the Centre has no role to play, as of today, in the funding of such schemes. However, I propose to have a detailed discussion with the Planning Commission in this regard and see if I could get some funding arrangements from the Centre. If I succeed, I hope I will be able to give the necessary assistance in such schemes. At this stage, however, it is not possible for the Centre to provide any assistance because there is no such policy at present.

[Shri Manubhai Kotadia]

As regards the Sone River system referred to by hon. Shrimati Kamlaji, I may mention that Rihand Dam was constructed in mid fifties. Another dam "Bansagar" is under construction.

As regards the Kadwan Dam Project report received in June, 1990, after getting examined by the Central Water Commission, has been returned to the State Government pointing out the deficiencies and requesting the State Governments to submit a modified project report, taking into consideration the suggestion and observations thereon.

Some hon. Members referred to dredging for desiltation. In this connection, I may mention that dredging carried out on experimental basis has not proved to be an effective solution except at the confluence of the river systems as the dredged rivers get silted up again during successive monsoons.

Members also suggested for pursuing the garland scheme linking various rivers to take care of floods. Though the schemes propounded by Dr. K. L. Rao and Dr. Dastur for inter-State transfer of surplus waters for irrigation and other purposes, was laundable and widely welcomed—I was also attracted and subscribed to the scheme even before I took up charge of the Ministry—...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR: What is the position, now?

SHRI MANUBHAI KOTADIA: Sir, I am coming to that point. It involves inter-State issues and huge investment. As point out by Shri Yadav, at present it requires one lakh and twently three thousand crores of rupees. Sir, up to the end of the Seventh Plan, right from First Plan to Seventh Plan, we have consumed forty three thousand crores of rupees in this sector. Only this scheme requires one lakh and ten thousand crores of rupees which I think is not possible to provide from our own resources. I had realised the gravity of the situation arising due to flooding of large areas of Bihar more or less on a recurrent basis soon after taking over the charge of the Ministry of Water Resources. As mentioned before, I had already discussed these issues with honourable Members of Parliamnet of Bihar and the Chief Minister of Bihar in May, 1990. I had also discussed these issues with the honourable Minister of Irrigation of Bihar. At this stage I would like to assure the honourable Members that I will extend full cooperation in this matter. Whatever my Ministry can do, it will do. The major constraint experienced by the Bihar State Government is inadequacy of funds. As I mentioned, the Ministry of Water Resources does not have any allocation in its annual budget for financing any specific flood central scheme. I have apprised the Prime Minister in July, 1990 regaring this particular situation and requested him for providing some funds to our Ministry as a special case, so as to provide Central assistance to the States for taking up critical schemes. I have also requested the Minister of External Affairs to take up the issue regarding cooperation in water resources development with Nepal at his level.

Flood control and management is a State subject and the onus to provide protection from floods rests with them and the Centre has no direct jurisdiction in the matter. Nevertheless, we would continue to do all that can be done by the Centre to mitigate the sufferings due to floods in Bihar.

In view of the position explained by me, I would request the honourable Shrimati Kamlajj to withdraw the Resolution proposed by her.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री जी का उत्तर काफी विस्तारपूर्वक आया । उन्होंने अपनी सद्इच्छा भी जाहिर की कि क्या करना चाहते हैं ।

सबसे पहले मैं इस प्रस्ताव पर बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूं । सबों ने अपने-अपने प्रांत की समस्याओं के बारे में अवश्य कहा, लेकिन साथ-साथ मूल प्रस्ताव के

ऊपर भी अपना विचार व्यक्त किया और बहुत सशक्त तरीके से अपनी बातों को कहा । मैं सब को धन्यवाद देती हूं ।

मंत्री जी ने अपने उत्तर में जिन बातों की चर्चा की, वह तो ठीक ही है, मूल प्रस्ताव के ऊपर आधारित ही उत्तर उनका रहा, लेकिन एक बात जिस पर उनका ध्यान नहीं गया, उसके ऊपर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं ।

बिहार में नदियां हिमालय से, नेपाल से आती हैं, यह बात सत्य है । उत्तर बिहार की बाढ़ की स्थिति उसी से उत्पन्न होती है और प्रति वर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है । मध्य बिहार में दूसरे प्रांतों की नदियों से बाढ़ आती है ।

इसमें मूल प्रस्ताव में नेपाल के साथ-साथ एक बात जिसकी ओर मैंने उल्लेख किया था, वह यह है कि अन्य प्रांतों से जैसे महानन्दा . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री मनुभाई कोटाडिया) : वह आपसे चर्चा करने के लिये तैयार हैं । यह उन्होंने कहा है । आप उनसे जो-जो बतायेंगी, वह और भी चर्चा करेंगे और बतायेंगे ।

श्रीमती कमला सिन्हा : नहीं, मैं बिल्कुल संक्षिप्त बात करूंगी । मैं जानती हूं और मंत्री जी ने जो कहा, ठीक ही है । उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ करने के लिये तैयार हूं ।

मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि महानन्दा नदी का जो तटबंध है, उसका खर्च का सारा बोझ बिहार पर पड़ता है और उससे लाभ पश्चिम बंगाल को होता है । तो सरकार को या तो यह निर्देश देना चाहिये कि जिस प्रांत के लिये वह ज्यादा फायदेमन्द हो, उस प्रांत को उसके रख-रखाव का इंतजाम करना चाहिये, अन्यथा केन्द्र सरकार उसके रख-रखाव का इंतजाम करें । एक तो यह बात है ।

दूसरी, इसी तरह की गंडक नहर की भी बात है । उत्तर प्रदेश के साथ वह जुड़ी हुई है । तो जिस हिस्से से उत्तर प्रदेश को लाभ होता है, पिपरासी बांध से उत्तर प्रदेश को ज्यादा फायदा होता है । तो उत्तर प्रदेश उसके रख-रखाव का काम करे । सारा रख-रखाव का, देखभाल का, तटबंधों का, इंबैंकमेंट का वह सारा बिहार सरकार के ऊपर बोझ न डाला जाय । क्योंकि होता यह हैं कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण हमारी योजना राशि का अधिकांश खर्चा सब बाढ़ से बचाव के काम में खर्च हो जाता है और अन्य विकास के काम बिहार सरकार कर नहीं पाती है और उसका लाजिमी नतीजा यह होता है कि बिहार की आज की पर कैपिटा इंकम हिन्दुस्तान से सबसे कम है । तो मैंने ये दो मुद्दे भी मंत्री जी के सामने रखे हैं । नेपाल के संबंध में इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वे नेपाल जायेंगे । इन्होंने उसमें थोड़ा "किन्तु" लगाकर कहा, मैं यह चाहूंगी उस "किन्तु" को हटा दें और यह कहें कि निश्चित रूप से नेपाल के साथ एक लांग टर्मproject एवंShort term project इस का नतीजा निकालने के लिये वार्ता होगी । यह दो उद्देश्य इस प्रस्ताव को लाने के पीछ मेरे थे । एक अल्पकालीन बाढ़ नियंत्रण का उपाय हो और एक दीर्घाकालीन बाढ़ नियंत्रण के उपाय आवश्यक हैं । जब तक नेपाल के साथ बात-चीत नहीं होगी तब तक यह काम संभव नहीं होगा । इसलिये मैं यह चाहती हूं कि मंत्री जी इसको जल्दी करें । अन्य जिन बातों की ओर मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा तो ठीक ही है । इसमें मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है । जल-जमाव के संबंध में उन्होंने कहा कि कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं तो उस कार्यक्रम को अगर वह जल्दी करवायें तो अच्छा रहेगा और टक्नोलोजी मिशन को जल्दी से जल्दी एक्टीवाइज करना चाहिये । 1987 में एक विशेष टास्क फोर्स भी गठित किया गया था जिससे कोसी और

[श्री मनुभाई कोटाडिया]

गंडक कमांड क्षेत्र में 224 करोड़ रुपये की योजना की मंजूरी दी थी तो उसको भी बिहार सरकार को उपलब्ध कराया जाए ताकि बिहार सरकार अपने काम को आगे बढ़ाये ।

लेकिन एक बात मैं अन्त में कहना चाहूंगी कि जब तक नदियों के सिल्टेशन को हटाने का काम नहीं होगा सारा जो भी काम बाढ़ नियंत्रण की दिशा में किया जायेगा वह कार्यक्रम विफल होगा । इसलिये सिल्टेशन को हटाने का काम अति आवश्यक है । यह भी उसी के साथ-साथ सत्य है कि सिल्ट हमेशा होता ही रहेगा क्योंकि हिमालय की नदियां चूंकि हिमालय सब से कम उम्र की पर्वत श्रृखला है और मिट्टी बहुत नदियां बहा कर लाती हैं और इससे सिल्टेशन होगा ही और सिल्टेशन को हटाना भी पड़ेगा ।

महोदय, ये दोनों ही बातें सत्य हैं तो माननीय मंत्री जी ये दोनों काम करने के लिये अगर आश्वासन देते हों तो मुझे अपना प्रस्ताव इन के अनुरोध पर, उसको वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मंत्री जी इसका आश्वासन दे दें ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Would you like to react, Mr. Minister?

SHRI MANUBHAI KOTADIA: I do not have to reply to anything. I have already assured that I will do my best.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Thank you very much. Sir, in view of what he has said, I will withdraw my Resolution.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

RESOLUTION REG. AFGHAN NATIONAL RECONCILIATION PROGRAMME.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Chaturanan Mishra to move his Resolution.

SHRI CHATURANAN MISHRA (Bihar): Sir, I beg to move the following Resolution:

"This House slpports the national reconciliation programme of President Najibullah of Afghanistan, urges upon all parties concerned to take appropriate measures to end blood-shed in Afghanistan, and appeals to the people all over the world to make their contribution for the cause of peace in the region."

उपसभाध्यक्ष महोदय, अफगानिस्तान में पिछले 10–12 साल से जो खून बह रहा है उससे सारा विश्व चिंतित है । सब से बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि जो लोग इस तरह के खून बहाने में अगुवाई कर रहे हैं, उसको एक सुपर राष्ट्र अमरीका की तरफ से पूरी मदद दी जा रही है और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान उसके लिए अपनी भूमि भी दे रहा है और वहां से उन लोगों को हथियारबद करके, ट्रेनिंग दे करके, अफगानिस्तान के अन्दर यह युद्ध चलाया जा रहा है ।

पाकिस्तान की कुछ ऐसी नीति है कि वह अफगानिस्तान में भी ऐसा कर रहा है और वह हमारे देश में भी उसी तरह की खुराफात काश्मीर और दूसरी जगहों में कर रहा है जिससे हम सभी अवगत ही हैं । यही नहीं, अभी कुवायत मसले पर उसने अमेरिका के कहने पर अपनी फौज सऊदी अरब में भी भेज दी है । पाकिस्तान इस तरह अपनी भूमि को बदनामी के काम के लिए इस्तेमाल करने दे रहा है । यह काफी चिंता की बात है । अभी जिस विषय की मैं यहां चर्चा कर रहा हूं, वह अफगानिस्तान के संबंध में है ।

अफगानिस्तान और भारत के बहुत पुराने संबंध हैं और दोस्ताना भी हैं । मैं आज से करीब 15 दिन पहले एक मिशन में काबुल गया था और हमारे